

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
(जनपद रुद्रप्रयाग को छोड़कर)  
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

विषय:- प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध करायें जाने तथा अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना इत्यादि मदों के अंतर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को एस.डी.आर.एफ. मानकों के अनुरूप तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने तथा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत आदि हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्नस्थापना तथा क्षमता विकास इत्यादि मदों के अंतर्गत व्यय हेतु संलग्न विवरणानुसार कुल ₹ 40.50 करोड़ (₹ चालीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में व्यय की जायेगी।
- 2- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों यथा-मार्गों एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबंधित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुएं, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापन कार्यों के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों में अनुमत्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से नियमानुसार आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।
- 4- मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी-

1. स्वीकृत धनराशि के व्यय में अद्यतन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा धनराशि का व्यय विवरण आपदावार शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायेंगे।
  2. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
  3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
  3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
  4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना नियमानुसार प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।
  5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
  6. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यों में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
  7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।
- 5— वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्यों में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- 6— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 7— क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों एवं हल्का वाहन मार्गों के प्रस्तावों पर वास्तविक क्षति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई एवं क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई अनुसार लो०नि०वि० द्वारा प्रति कि०मी० सड़क निर्माण हेतु

निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु मूल आगणन के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

8— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के जिला पंचायत, विकास खण्ड एवं स्थानीय निकाय आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्राप्त आगणनों, जहां अधिशासी अभियन्ता स्तर के अभियन्ता न हो, वहां लो०नि०वि० के अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित/सत्यापित कर, दरें प्रतिहस्ताक्षरित करायी जाए।

9— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित नवीन मद एवं मानकों से आच्छादित होने एवं निर्धारित समयावधि के अन्दर क्षति होने की पुष्टि तथा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति के बाद ही कार्य योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

10— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

~~11— कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमत्य नहीं होगा। कार्य करते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।~~

12— कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर राज्य आपदा मोचन निधि से निर्मित कार्ययोजना का नाम, लागत, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कॉक्रीट/बोर्ड पर अंकित कर दिया जाए।

13— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800- अन्य व्यय-00-13-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

15— यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०पत्र संख्या-184 NP/वित्त अनु०-5/2016, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,


(अमित सिंह नेगी)

सचिव

संख्या-2821 (1)/XVIII-(2)/16-12(4)/2013 TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

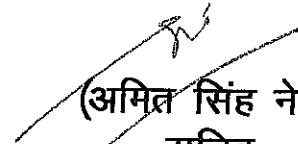
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, (जनपद रुद्रप्रयाग को छोड़कर)।
- 8- निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 9- निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- ~~वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।~~
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
 (संतोष बड़ोनी)  
 उप सचिव

शासनादेश संख्या-2821/XVIII-(2)/2016-12(4)/2013T.C., दिनांक 15 दिसम्बर, 16  
2016 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
1	उत्तरकाशी	5.00
2	चमोली	5.00
3	टिहरी गढ़वाल	5.00
4	पिथौरागढ़	5.00
5	पौड़ी गढ़वाल	4.00
6	नैनीताल	3.00
7	अल्मोड़ा	3.00
8	बागेश्वर	2.50
9	देहरादून	2.00
10	हरिद्वार	2.00
11	उधमसिंहनगर	2.00
12	चम्पावत	2.00
	कुल योग	40.50

(₹ चालीस करोड़ पचास लाख मात्र)

  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव